मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1251. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या क़दम उठाए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है;

(घ) मध्य प्रदेश में रूग्ण खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मध्य प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वयं कोई आंकलन नहीं करता। लेकिन मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकारों, संस्थानों और संगठनों को ऐसे सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस प्रकार के अध्ययन के सिलसिले में मध्य प्रदेश की सरकार/संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूँजी-निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतियों को उदारीकृत किया है और अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया है। घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय पूँजी-निवेश को बढ़ावा देने, वित्तीय रियायतें उपलब्ध कराने आदि जैसे विभिन्न अन्य उपाय भी किए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए सभी उद्योगों की संख्या, इनमें रुग्ण उद्योग भी शामिल हैं को राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। रुग्ण यूनिटें पुन: चालू/बन्द होने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सम्पर्क कर सकती है।

Funds for Development of Women and Children in Gujarat

1252. SHRIMATI URMILABEN CHIMAN-BHAI PATEL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is any programme for development of women and children in rural areas of Gujarat;

(b) if so, the funds released by the Central Government under this programme during the last three years;

(c) whether the Gujarat Government has requested for more funds for this purpose; and

(d) if so, what is Government's reaction thereto and the future programme of the State Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir. The Ministry of Rural Areas and Employment is implementing the Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) programme in the rural areas of Gujarat.

(b) Central funds amounting to Rs. 2.68 crores were released to various DRDAs of Gujarat under the programme during the last three years.

(c) and (d) Yes, Sir. A request has been received from the State Government a few days ago for additional sanction of 2000 groups over and above the allocation for 1033 groups f-3 for this year. The same is under consideration.

Gas Reserves in India

1253. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned "India has massive gas reserve", published in the Financial Express dated the 24th March, 1996;

(b) whether the Texas-based Geoscientist, Mr. N. Mokogon, has been furnished with the seismic data for assessing the gas reserves, reportedly lying below the waters of the Arabian Sea and the Bay of Bengal;